भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1131
बुधवार, 13 दिसंबर, 2023 / 22 अग्रहायण , 1945 (शक) को उत्तरार्थ

कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) का कम्प्यूटरीकरण

1131. **श्रीमती गीता उर्फ़ चन्द्रप्रभा:**

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) के कम्प्यूटरीकरण की दिशा में काम कर रही है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है ?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ख): दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) में राज्य और प्राथमिक स्तरों पर सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक शामिल हैं, जो मुख्य रूप से किसानों को दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने में कार्यरत हैं। अभी तक, 13 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में कार्यात्मक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) विद्यमान हैं।

सरकार ने 119.40 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) की परिचालन दक्षता में सुधार लाने, उधार देने, वसूली और संसाधन जुटाने में अपनाई जाने वाली प्रणालियों के लेखांकन प्रथाओं और मुख्य पहलुओं में एकरूपता लाने और उनके व्यवसाय के विस्तार में सहायता हेतु 1,851 इकाइयों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को मंजूरी दे दी है।

इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी नाबार्ड है, जिसके द्वारा एआरडीबी के लिए एक कॉमन राष्ट्रीय स्तर का सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा । इस परियोजना के तहत हार्डवेयर, लीगेसी डेटा के डिजिटलीकरण के लिए सपोर्ट, कर्मचारियों को प्रशिक्षण, आदि प्रदान किया जाएगा ।

इस संबंध में, मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 16.11.2023 को परियोजना के दिशा-निर्देश परिचालित किए जा चुके हैं व संबंधित राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों से परियोजना हेतु प्रस्ताव भी मांगे जा चुके हैं।

*****